राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को मान्यता दिए जाने में विसंगति

1996. **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन जातियों और जनजातियों के नाम क्या हैं जिन्हें एक राज्य में तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता प्राप्त है, परन्तु अन्य राज्यों में उन्हें ऐसी मान्यता नहीं दी गई है ; और

(ख) क्या सरकार अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जन-जातियों को मान्यता दिए जाने के मामले मे एक रूपता लाने के लिये निकट भविष्य में एक सर्वेक्षण करने का विचार रखती है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) यह सूचना विधि तथा न्याय मंत्रालय द्वारा प्रकाशित चुनाव विधि नियमावली के नवीनतम संस्करण में दी गई है । अनुवर्ती परिवर्धन इस प्रकार है :—

(i) मेघालय में अनुसूचित जनजाति की सूची में निम्नलिखित तीन समुदायों को शामिल करना :

1. बोरो कचारी
2. कोच
3. राबा, रावा

(ii) जम्मू तथा कश्मीर राज्य में आठ समुदायों को अनुसूचित जनजाति घोषित करना :—

1. बाल्टी, 2. बेडा, 3. बोट, बोटो 4. ब्रोपका, ड्रोपका, डर्ड, शिन, 5. चंगपा, 6. गारा 7. मोन् 8. पुरीगपा

(iii) नवीनतम "संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990 के अनुसार अनुसूचित जातियों का विनिर्दिष्ट करने वाले आज तक जारी सभी राष्ट्रपति आदेशों में "हिन्दू)" अथवा "सिक्ख" शब्द के बाद "बौद्ध" शब्द जोड़ा गया हैं ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

Manufacture of 12 horse power tractors

1997. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI KAPIL VERMA;
SHRiBHUVNESH CHATURVEDI:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the former Deputy Prime Minister initiated a proposal for mass production of a small 12 horse power tractor on Chinese model which he had seen [m] China and also to import 5000 such tractors in the country;

(b) if So, what action Government have taken thereon; and

(c) whether it is also a fact that Ministry of Finance is not agreeable to the proposal?

THE MINISTER OF STATEMENT THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): (a) No, Sir. There is no proposal for mass production or import of small tractors. However, some Indian manufacturers have the capacity to make such small tractors.

(b) and (c) In view of the reply to Part (a), the Question does not arise.

Revision of procurement policy

1998. SHRI SURESH PACHOTJRI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether new procurement policy announced on the 18th July, 1990 is likely to be revised in the light of